डाक विभाग द्वारा योजनाओं को लागू न किया जाना

1710. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "डाक-तार विभाग की योजनाएं चार महीने ठप्प" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी हां। 14 जुलाई, 1996 के नवभारत टाइम्स में संबंधित न्यूज आइटम डाक विभाग के कार्य पर एक अनुमानित टिप्पणी है, जिसके समर्थन में तथ्य नहीं दिए गए हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए गए संबंधित वार्षिक प्लानों के अनुसार विभाग के विकास कार्यक्रम विधिवत् रूप से कार्यान्वित किए गए हैं। चालू वर्ष 1996-97 के दौरान, योजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन वित्त वर्ष के प्रथम चार महीनों के लिए लेखानुदान के माध्यम से आरम्भ में सुलभ कराए गए संसाधनों के अनुरूप है। डाक काउंटरों के कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम गत तीन वर्षों के दौरान अच्छा चल रहा है हालांकि योजना अवधि के आरंभिक दो वर्षों के दौरान प्रारंभिक कठिनाइयों के कारण इसकी गति धीमी रही। फंड की कमी के कारण विभाग ने कोई भी विकासात्मक कार्यक्रम रोका या स्थगित नहीं किया गया। अधिकांश डाक सेवाओं द्वारा अर्जित राजस्व प्रचालन लागत की पूर्ति करने में अपर्याप्त है। इसलिए विभाग को उपयुक्त फंड के लिए आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान की गई है।

जहां तक वर्ष 1996-97 में नए डाकघर खोलने का संबंध है विभाग का 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 150 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है और संबंधित सर्किलों को इनका आवंटन कर दिया गया है। डाकघर मानदंडों की पूर्ति होने और संसाधनों की उपलब्धता पर ही खोले जाएंगे। अब तक चालू वर्ष के दौरान 20 विभागीय शाखा डाकघर तथा दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किए जा चुके हैं। पंचायत संचार सेवा केन्द्रों के संबंध में चालू वर्ष के लिए 250 का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को भी सर्किलों को आवंटित कर दिया गया है, इसमें जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 60 केन्द्र शामिल हैं। नए डाकघर खोलने के संबंध में विभाग के योजना लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्यवाही चल रही है।

विभाग सरकार के मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों का भी अनुपालन कर रहा है। डाक दरों के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया सरकार की वार्षिक बजट प्रक्रिया का नियमित अंग है।

Statutory Development Board for Konkaa region of Maharashtra

1711. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the decision taken by Government on the proposal for setting up a Statutory Development Board for Konkan Region of Maharashtra; and

(b) by when the requisite legislation for amendment of the Consitution is likely to be brought before Parliament?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD: MAQBOOL DAR): (a) and (b) The matter is under consideration. Keeping in view the legal and constitution complexities involved in the issue, it would not be possible to lay down a definite time frame to finalise it.

अमरीका द्वारा भारतीय ऊनी वस्त्रों पर रोक लगाया जाना

1712. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका और कुछ यूरोपीय देशों ने भारत में निर्मित ऊनी परिधानों के आयात पर एकतरफा रोक लगाने की घोषणा की है;

(ख) विश्व व्यापार संगठन इस संबंध में दोनों देशों के बीच एक बैठक आयोजित करने का विचार रखता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) विश्व व्यापार संगठन द्वारा दोनों देशों के बीच ऐसी बैठक का आयोजन कब तक किये जाने की संभावना है?